Statement

Sl.No	Name of Foreign Collaborator	Item of Manufacture
1	Givaudan Roure, Switzerland	Perfume/flavour compound
2	Bata (BN) BV, Netherlands	Footwear, leather products and garments
3	The Wait Disney Co., USA	Music cassettes, toys educational held & video products
4	Levi's Strauss & Co., Hong Kong	Garments
5	littlewoods International Ltd., UK	To set up a 100% owned subsidiary for International marketing and vendor development for Indian made products.
6	Benetton Group S.p.a., Italy	Garments
7	Dunkin'Donuts Inc. USA	To set up a joint venture for establishing outlets for marketing of Dunkin Donuts products.
8	Baskin Robbins International Ltd., USA	Ice-cream
9	Anway Corporation, Michigan, USA.	Products sourced from local independent Indian manufacturers particularly SSI Units.

MR. CHAIRMAN; The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

1980 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों का विकास

*124. श्री आस मोहम्मद :
श्री ईश दत्त यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1980 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत न तो अपेक्षित रोजगार अवसरों में पिछड़े हुए क्षेत्रों का सन्तुलित विकास हुआ है और न ही कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या 1980 से 1994 तक की अवधि के दौरान औद्योगिक नीति के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं और कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना की गई है ; और

(ग) क्या वर्तमान नीति इन समस्याओं के निराकरण में सहायक होगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) 1980 के औद्योगिक नीति संबंधी व्यक्तव्य के अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना और कृषि पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देकर कृषि के आधार को सुदृढ़ बनाना, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का विकास प्राथमिकता के आधार पर करके क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना तथा अन्तर-क्षेत्रीय संबंधों का संवर्धन करना, सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य थे । वस्तुतः देश की औद्योगिक नीति हमेशा ऐसे ही उद्देश्यों से संचालित होती रही है। जुलाई 1991 के औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में भी लाभकारी रोजगार पर जोर दिया गया है। कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास के उद्देश्य से लगभग सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अब लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। विद्यमान औद्योगिक नीति से निश्चित रूप से रोजगार के और अधिक अवसर पैदा होंगे।